

बिहार में लघु उद्योगों की दशा और दिशा पर विशेष वाद-विवाद

21.7.2000

श्री सरयू राय : सभापति जी, माननीय सदस्य, श्री रामकृपाल जी बहुत प्रसन्न होंगे। 10 वर्षों से उनके दल की सरकार यहां चल रही है। जब पहली बार 1990 में बजट भाषण हुआ था जिसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा था कि बिहार राज्य में उद्योग के विकास में तीव्रता लाने के लिए बिहार के बाहर के उद्योगपतियों को बिहार में जाल बिछाने के लिए राज्य के मूल हित को ध्यान में रखते हुए प्रोत्साहित किया जाएगा। राज्य के औद्योगिक विकास के कार्यक्रम को इस तरह से कार्यान्वित किया जाएगा कि जिससे रोजगार का अधिक अवसर उपलब्ध हो सके। उसके बाद के वर्षों में हर साल ऐसा ही 1993-94 के बजट भाषण में उन्होंने कहा था कि आगामी वित्त वर्ष में नये औद्योगिक प्रस्ताव के तहत एक अप्रैल, 93 से 31 मार्च, 98 तक उत्पादन में आने वाले औद्योगिक इकाइयों को आवश्यक सहायता दी जायेगी इसके अतिरिक्त राज्य के 11 लघु और ग्रामीण इकाइयों को स्थापित किया जायेगा उसके बाद 96-97 के बजट भाषण जो उन्होंने दिया था तो उस समय 1995 में एक औद्योगिक नीति सरकार ने घोषित कर दिया था और फर्क के साथ कहा था राज्य में औद्योगिकीकरण में तीव्रता लाने हेतु पहली अगस्त, 95 से नयी औद्योगिक नीति की घोषणा के क्रम में देश के विभिन्न वाणिज्य केन्द्रों पटना, दिल्ली, बम्बई, कलकता आदि के औद्योगिकपतियों से विचार विमर्श किया गया, गहन विचार विमर्श के फलस्वरूप पेपर, तेल, सिगरेट, चाय, उर्जा, खाद्य आदि में 15.500 करोड़ के पंजी निवेश के आकर्षित करने हेतु सिंगापुर, थाइलैंड, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, इंग्लैंड में औद्योगिक अभियान चलाया गया और उसके बाद कहा था इसका प्रतिफल शायद बना रहे होंगे। रूग्ण एवं बंद इकाइयों के पुर्नवास हेतु मध्यम तथा लघु उद्योग क्षेत्र में सिर्फ राज्यस्तरीय समिति का गठन किया गया है। अब माननीय मंत्री महोदय बतायेंगे कि राज्यस्तरीय समितियों ने कितनी प्रगति की। महोदय, 1990 से अबतक दुनिया कहां से कहां चली गई सूचना और औद्योगिकीकरण का विस्तार हुआ हम तब से हर तरह के उद्योगों में वही के वही रहते तभी एक बात थी कितना पीछे हम चले गए, इसकी कल्पना करना मुश्किल है। शायद मंत्री महोदय बता सकेंगे, तो आज ऐसी स्थिति में हमलोग विचार कर रहे हैं। यानि उद्योगों के कब्रगाह पर बैठ कर हम उद्योग के विकास की चर्चा कर रहे हैं आज विकास की स्थिति क्या होगी, उसके बारे में माननीय सदस्य ने कहा विकास की दिशा क्या होनी चाहिए। आज भी समय बहुत बीत गया है फिर भी हमें सचेत होना चाहिए कि जो चुनौतियां हमको दुनिया भर से मिल रही हैं।

और हमारे यहां क्या हो रहा है। मुझे बहुत तकलीफ हुई, एक राजनीतिज्ञ जो इस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनका अखबारों में बयान छपा, टी.वी. पर उन्होंने इंटरव्यू दिया कि कम्प्यूटर-उम्प्यूटर क्या होता है। इससे क्या होने वाला है। एक तरफ जो इस राज्य को चलाने वाले हैं, वे ऐसी चीजों के बारे में जो लघु उद्योग नहीं बल्कि कुटीर स्तर के उद्योग में भी जो उपयोग होने वाला है। तकनीकी के बारे में अगर इस तरह की अपेक्षा का भाव कह कर कोई बात करे या तो उसको जानकारी का अभाव हो सकता है। यहां तो देश दुनिया घूमने के बाद वृहद राजनीतिक अनुभव प्राप्त करने के बाद भी उनकी आंखें नहीं खुली हैं। कोई सोया हुआ नहीं है, जगा हुआ है तब उसे जगाने की बात किया जाय। तो आज यह स्थिति है तो सरकार

इनकी दिशा निर्देश में चल रही है । मैं इतना ही अर्ज करूंगा कि जो दुनिया भर की चुनौतियां मिल रही हैं, दुनिया भर में वैश्वीकरण, बाजीकरण की सूचना प्रावैधिकी है उसमें हम अब लघु उद्योगों को कैसे विकसित करेंगे । मैं संरक्षण देने की बात नहीं कर रहा हूँ । आज बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की नजर हमारे बाजार पर लगी हुयी है । इसलिए लघु उद्योग की सीमा बढ़ाई जाय यह प्रयास होना चाहिए । इसमें एक बार सफल भी हो गये थे । हम तीन करोड़ तक आ गये थे । मगर गनीमत है कि उसको घटा दिया गया, सरकार सचेत हुई, सरकार ने घटा दिया । तो यह समग्र चुनौतियां आ रही है, उसमें महात्मा गांधी के समय से लघु उद्योग के बारे में कहा जा रहा है, उससे कितना रोजगार का सृजन हुआ, कितने हाथ को काम मिला है । तो आज हम कैसे तालमेल बैठायेंगे, इसके बारे में ठोस नीति होनी चाहिए । आवश्यकता सरकार समझती है तो एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी चाहिए । 10-15 साल आगे के बारे में हम सोचें, चिन्ता करें तब शायद हम इस राज्य का कुछ भला कर सकते हैं । महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद ।

.....